डॉ.चतुर्वेदी ने मार्शल आर्ट में मेडल विजेताओं का उत्साह बढ़ाया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.अरुण चतुर्वेदी से बुधवार को उनके सरकारी आवास पर मार्शल आर्ट में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच रमेश चौधरी ने मुलाकात की।

जयपुर, (का.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को सरकारी आवास पर मार्शल आर्ट मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने कोच रमेश चौधरी के साथ मुलाकात की।

डॉ. चतुर्वेदी ने मैडल प्राप्त खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर देश-प्रदेश का नाम रोशन करें। 16वीं मुम्बई जूनियर-सब जूनियर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो 23 से 31 मई 2015 को बैंगलोर में आयोजित की गई थी।

प्रतियोगिता में राजस्थान सहित देश के अन्य 18 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 गोल्ड तथा 11 सिल्वर एवं 2 ब्रॉन्ज मैडिल हासिल किये हैं। इस सीजन में पहली बार हुआ जो राजस्थान को इतने सारे मैडल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्राप्त हुए हैं। प्रतियोगिता में 10 से 12, 12 से 15 एवं 15 से 18 आयु वर्ग की प्रतिभागियों ने भाग लिया था तथा बेस्ट फाईटर की ट्राफी जयपुर के लक्केश शर्मा को प्रदान की गई है।

डॉ. चतुर्वेदी ने की जनसुनवाई

जयपुर, (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं सिविल लाईन विधायक डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने मंगलवार देर शाम को किशन नगर, श्याम नगर एवं जनपथ कॉलोनियों का दौरा कर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने का विश्वास दिलाया।

इस मौके पर डॉ. चतुर्वेदी ने कॉलोनीवासियों को बताया कि श्याम नगर क्षेत्र में सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है जो जल्दी पूरा हो जायेगा। जिसका लाभ कॉलोनी वासियों को मिलेगा।

भ्रमण के दौरान डॉ. चतुर्वेदी ने कॉलोनियों के लोगों के साथ वृक्षारोपण भी किया तथा लोगों को आह्वान किया कि कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिये जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहे। उधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को सरकारी आवास पर विधान सभा क्षेत्र के लोगों की पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन आदि जन समस्याओं को गम्भीरता से सुना और दूरभाष पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिये।

निशक्तजनों की परेशानी दूर करेगा कंपोजिट रीजनल सेंटर

पांच एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, 15 करोड़ का बजट स्वीकृत

जयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

निशक्तजनों की सभी मुश्किलों का हल जल्द होने वाला है। राजधानी में विशेष योग्यजन के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) बनेगा। इसके लिए कलक्टर ने विशेष योग्यजन निदेशालय के जामडोली में बने स्वयंसिद्धा भवन में सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्र सरकार ने सेंटर के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। खास बात है कि इस सेंटर में कृत्रिम अंग व उपकरणों का निर्माण भी किया जाएगा।

विशेष योग्यजन निदेशालय के निदेशक पी.आर.पण्डित ने बताया कि कंपोजिट रीजनल सेंटर का भवन निर्माण होने तक, जामडोली में ही विमंदित गृह के प्रशासनिक भवन में सेंटर चलेगा। भवन निर्माण होते ही सेंटर को शिफ्ट कर दिया जाएगा।

मिलेंगी ये सुविधाएं : सेंटर में मानसिक और शारीरिक निशक्तजन को चिकित्सा, व्यायाम, प्रशिक्षण व फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लोगों को जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं प्रशिक्षित लोगों को स्वरोजगार सृजित करने के लिए ऋण की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा विशेष योग्यजन को कृत्रिम अंग भी लगाए जाएंगे।

अभी यहां : पटना, सुंदरनगर, भोपाल, गुवाहाटी, श्रीनगर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोझीकोड में सीआरसी चल रहे हैं।

newsbrief

मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं

जयपुर @ पत्रिका. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन आदि से जुड़ी समस्याएं सुनी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश भी दिए। इसके अलावा चतुर्वेदी ने किशन नगर, श्याम नगर एवं जनपथ की कॉलोनियों का दौरा कर लोगों से उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने पानी, सड़क व अन्य समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का भरोसा दिलाया।

आरक्षण विधेयक में न हो क्रीमीलेयर का प्रावधान

▸ एसबीसी आरक्षण ड्राफ्ट कमेटी की पहली बैठक में गुर्जर प्रतिनिधियों ने उठाया मुद्दा

जयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित विधेयक में क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं करने की मांग उठाई है। विधेयक तैयार करने के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी की बुधवार को शासन सचिवालय में हुई पहली बैठक में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने यह मांग प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जब सरकार उन्हें विशेष पिछड़ा मान रही है तो वे क्रीमीलेयर कैसे हो सकते हैं।

बैठक में आरक्षण विधेयक के मसौदे पर कमेटी के सदस्य मंत्रियों व गुर्जर प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श किया। इस दौरान समाज की ओर से कहा गया कि सरकार को विधानसभा में पेश करने के लिए एक प्रभावी विधेयक तैयार करना चाहिए। बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना, गुर्जर प्रतिनिधि कर्नल किरोड़ी बैंसला, हिम्मतसिंह, एडवोकेट शैलेन्द्रसिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी, कार्मिक विभाग के शासन सचिव आलोक गुप्ता, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता मौजूद थे। राठौड़ ने बैठक के बाद कहा कि सरकार की मंशा आरक्षण विधेयक शीघ्र तैयार कर इसे विधानसभा में पारित करवाने की है। विधेयक को बेहतर बनाने के लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे।

ये भी दिए सुझाव

- पदोन्नति में भी लागू हो आरक्षण।
- महाराष्ट्र में 2001 से लागू आरक्षण की तर्ज पर बनाया जाए प्रभावी विधेयक।
- गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में गुर्जर समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोके सरकार।

डेली न्यूज 11.6.15

आरक्षण बिल पर मंथन शुरू

विशेष पिछड़ा वर्ग को अलग से पांच फीसदी आरक्षण देने का मामला

गुर्जर प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल की उपसमिति की पहली बैठक में बिल का प्रारूप बनाने पर हुई चर्चा

डेली न्यूज ब्यूरो जयपुर। 10 जून

प्रदेश में विशेष पिछड़ा वर्ग को निर्धारित आरक्षण से अलग पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए बिल का प्रारूप बनाने पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई। सचिवालय में आयोजित बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना के अलावा गुर्जर आरक्षण मंच के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह और एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह ने भाग लिया।

विशेष पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए बनाये जाने वाले बिल की ड्राफ्ट कमेटी की इस पहली बैठक में प्रभावी आरक्षण बिल तैयार करने पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में गुर्जर समाज की ओर से किरोड़ी बैंसला, हिम्मत सिंह एवं एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह ने बनाये जाने वाले आरक्षण बिल के ड्राफ्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की एवं सुझाव दिये। बैंसला ने आरक्षण बिल लाने के लिए सरकार को महाराष्ट्र पैटर्न अपनाने का सुझाव दिया। इस पर मंत्रिमंडल उपसमिति की ओर से और सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर आगामी बैठक में चर्चा होगी।

चिकित्सा मंत्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी विशेष पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए प्रभावी बिल तैयार कर विधानसभा में पास किया जा सके। कार्मिक विभाग के सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आरक्षण बिल बनाने में सभी के सुझाव एवं सहयोग लिया जायेगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की उपसमिति और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक बिल बनाने पर सहमति हुई थी। इस बिल का प्रारूप राज्य सरकार और आरक्षण समिति के मनोनीत सदस्यों के बीच आपसी चर्चा के बाद तैयार होना है। इसके लिए बुधवार को पहली बैठक आयोजित की गई।

इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसे सदन की ओर से पारित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र कुमार गुप्ता, कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) ओ.पी. गुप्ता एवं विधि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

हज शिविर 17 को

राज्य से हज यात्रा-2015 पर जाने वाले यात्रियों के लिए 17 जून को करबला स्थित हज हाउस में शिविर लगाया जाएगा। बुधवार को शासन सचिवालय में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हज यात्रा-2015 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि हज हाउस में जयपुर जिले के हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जाएगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अब तक की हज गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मंत्री ने आगामी गतिविधियों के कुशल संचालन के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अति. मुख्य सचिव विपिन चंद शर्मा, निदेशक शकुंतला सिंह, संयुक्त सचिव अकील अहमद, राज. हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी खान मोहम्मद आदि मौजूद थे।

पंजाब केसरी – 11.6.15

महाराष्ट्र पैटर्न पर गुर्जरों को आरक्षण

कमेटी करेगी अध्ययन

-बिल का ड्राफ्ट बनाने पर मंथन

- गुर्जर नेताओं ने कहा, बिल में हो मजबूत आधार

जयपुर, (कासं): गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न पर विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बिल में पदोन्नति में रिजर्वेशन, क्रीमिलेयर लागू नहीं होगा। बुधवार को यहां शासन सचिवालय में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भडाना की उपस्थिति में विशेष पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए बनाए जाने वाले बिल की ड्राफ्ट कमेटी की पहली बैठक हुई।

बैठक में प्रभावी आरक्षण बिल तैयार करने पर मंथन किया गया। बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह एवं एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह ने बिल के ड्राफ्ट को लेकर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की एवं सुझाव दिए। बैठक में गुर्जर नेताओं ने कहा कि पुराने बिल में खामियों को दूर करके नया विधेयक बनाया जाए तथा पुरानी कमेटियों और ओबीसी के रिजर्वेशन का अध्ययन किया जाएगा। बैठक में कार्मिक विभाग के शासन सचिव आलोक गुप्ता ने आरक्षण बिल के लिए बनाए गए ड्राफ्ट के प्रारूप पर चर्चा करते कहा कि आरक्षण बिल बनाने में सभी का सुझाव एवं सहयोग लिया जाएगा।

सुझाव देंगे, कमेटी में नहीं रहेंगे गुर्जर नेता

ड्राफ्ट बिल तैयार करने वाली कमेटी में गुर्जर नेता नहीं रहेंगे। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बताया कि आरक्षण बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी में समाज के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। समाज की ओर से सिर्फ सुझाव दिए जाएंगे। इसके लिए विधि सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें डीओपी सचिव, एएजी समेत अन्य उच्चाधिकारी शामिल होंगे।

ताकि नहीं आए दिक्कत

बैठक में तय किया गया कि आरक्षण बिल तैयार करते समय राज्य में 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण प्रावधान के लिए मजबूत आधार बनाया जाएगा ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। गुर्जर नेताओं ने कहा कि जहां भी 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण लागू है वहां की स्टडी करके गुर्जरों को आरक्षण मिलने का मजबूत आधार दिया जाए, इसके लिए पुरानी कमेटियों की भी रिपोर्ट और ओबीसी रिजर्वेशन का अध्ययन किया जाए।

मुकदमों पर चिंता

सिकन्दरा व सवाईमाधोपुर में दर्ज मुकदमों को लेकर बैठक में गुर्जर नेताओं ने चिंता जताई। गुर्जरों ने सिकन्दरा का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान माली व गुर्जरों में विवाद हुआ। सरकार को चाहिए

▸ शेष पृष्ठ [illegible] पर

चतुर्वेदी ने सुनीं जन समस्याएं

जयपुर, (कासं): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को सरकारी आवास पर विधान सभा क्षेत्र के लोगों की पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन आदि जन समस्याओं को गम्भीरता से सुना और सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से प्रभावी तरीके से समाधान करने का निर्देश दिए। उन्होंने वार्ड नं. 23 में एसटीएफ के तहत नवनिर्मित हॉस्टल [illegible] का विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत वितरण निगम के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिए। इसी तरह विभिन्न वार्ड पार्षदों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम के अधिकारियों से बात की।

कॉलोनियों में भ्रमण कर सुनी समस्याएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं सिविल लाइन्स विधायक डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने मंगलवार देर शाम किसान मार्ग, श्याम नगर एवं जनपथ कॉलोनियों का दौरा कर लोगों से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का विश्वास दिलाया। भ्रमण के दौरान डॉ. चतुर्वेदी ने कॉलोनियों के लोगों के साथ पौधारोपण भी किया। उनके साथ वार्ड पार्षद गुलाब [illegible], पूर्व पार्षद हरीश शर्मा व पीयूष उपाध्याय, लोकेश जैन, बृजकिशोर, [illegible] सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मार्शल आर्ट में मेडल विजेता मिले

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी से बुधवार को सरकारी आवास पर मार्शल आर्ट में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने कोच रमेश चौधरी के साथ मुलाकात की। 16वीं मुथाई जूनियर-सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो 23 से 31 मई को बैंगलुरू में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 गोल्ड तथा 11 सिल्वर एवं 2 ब्रॉन्ज मैडल हासिल किए हैं। यह इतिहास में पहली बार है जब राजस्थान को इतने सारे मैडल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्राप्त हुए हैं। प्रतियोगिता में बेस्ट फाइटर की ट्रॉफी जयपुर के लक्ष्केश शर्मा को प्रदान की गई है।

समाचार जगत 11-6-15

विशेष पिछड़े वर्ग के लिए बिल में बताई खामियां

जयपुर (कासं)। शासन सचिवालय में बुधवार को विशेष पिछड़े वर्ग में आरक्षण देने के लिए बनाए जाने वाले बिल की ड्राफ्ट कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रभावी आरक्षण बिल तैयार करने पर व्यापक चर्चा की गई। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व में तैयार किए गए बिल में खामियां बताई तथा व्यापक सुझाव दिए। बैठक में गुर्जर प्रतिनिधियों का कहना था कि बिल महाराष्ट्र पैटर्न पर बने, जिसमें पचास फीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने के पूरे मापदण्ड समाहित हों। पुरानी कमेटियों की रिपोर्ट की खामियों को दूर किया जाए। गुर्जर नेताओं का कहना था कि हम कमेटियों के पार्ट नहीं होंगे। हम सुझाव देंगे, जिससे कि विशेष पिछड़े वर्ग के लिए बनने वाला आरक्षण बिल का सर्वश्रेष्ठ ड्राफ्ट तैयार हो। बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी विशेष पिछड़े वर्गों को

शेष पृष्ठ 4 पर

विशेष पिछड़े वर्ग के लिए...

आरक्षण देने के लिए प्रभावी बिल तैयार कर विधानसभा में पास किया जा सके। बैठक में सामाजिक न्यायमंत्री डा. अरुण चतुर्वेदी, खाद्य व आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना, गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह, शैलेन्द्र सिंह एडवोकेट, कार्मिक सचिव आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र गुप्ता व कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव ओपी गुप्ता व विधि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

द० भास्कर - 11-6-15

गुर्जर आरक्षण : बिल के प्रभावी ड्राफ्ट पर मंथन

पहली बैठक में तीन मंत्रियों के साथ शामिल गुर्जर नेता

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

गुर्जर सहित विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को आरक्षण देने के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी की पहली बैठक में सरकार के तीन मंत्रियों के साथ गुर्जर नेता भी शामिल हुए। कमेटी ने प्रभावी आरक्षण बिल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की।

बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना शामिल रहे। वहीं, गुर्जर समाज की ओर से किरोड़ी लाल बैंसला, हिम्मत सिंह एवं एडवोकेट शैलेंद्र सिंह शामिल रहे। मंत्रियों ने गुर्जर नेताओं के साथ आरक्षण बिल के ड्राफ्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि विशेष पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जल्दी प्रभावी बिल तैयार कर विधानसभा में पास किया जा सके। कार्मिक विभाग के सचिव आलोक गुप्ता ने ड्राफ्ट के प्रारूप पर चर्चा करते कहा कि आरक्षण बिल बनाने में सभी के सुझाव एवं सहयोग लिया जाएगा। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र कुमार गुप्ता, कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) ओ.पी. गुप्ता एवं विधि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मदरसों में 20 बच्चे से कम तो पंजीयन होगा निरस्त

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात विभाग प्रदेश के मदरसों का भौतिक सत्यापन करेगा। इसमें शून्य और 20 बच्चों से कम नामांकन वाले मदरसों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के समायोजन, स्थायीकरण, सम्मान योग्यता निर्धारण एवं समान अनुबंध शर्तों के संबंध में बैठक ली। डॉ. चतुर्वेदी ने अल्पसंख्यक मामलात के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मदरसा बोर्ड में कार्यरत शिक्षा सहयोगी के मानदेय के प्रकरण को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शून्य बच्चों वाले एवं 20 बच्चों से भी कम नामांकन वाले मदरसों का पंजीयन नीति के अनुसार पंजीकरण निरस्त करने के निर्देश दिए।

योजना- समाज कल्याण के हॉस्टलों में खाद्य सामग्री सप्लाई करेगी कानफेड

जयपुर। समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में खाद्य सामग्री की सप्लाई का जिम्मा अब राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) को सौंपा गया है। गुणवत्तायुक्त व समान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था होगी। छात्रावास संचालक अपने स्तर पर बाजार से राशन की खरीद नहीं कर सकेंगे। इससे अनियमितताएं भी रुकेंगी। डायरेक्टर अंबरीश कुमार ने अधिकारियों के छात्रावास के लिए बाजार से खाद्य सामग्री की खरीद करने पर रोक लगा दी।